RAJYA SABHA

Friday, the 17th August, 1990|26
Sravana, 1912 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman in the Chair.**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, happy birthday to you.

SHRI A. G. KULKARNI: Happy birthday. At least acknowledge.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. But my birthday is not today.

SHRI P. SHIV SHANKER: Sir, in anticipation, you may accept. We will come on Sunday.

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : सब को आशीर्वाद दो।

श्री सभापति : आप बुजुर्ग हो ... (**व्यवधान**)

डा० शंकर दयाल पाण्डेय : माननीय सभापति जी, हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री बलराम सिंह जी यादव को इटावा में कल गिरफ्तार कर लिया गया है।... (**व्यवधान**) बड़े दुःख की बात है ... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I will announce it after the Question Hour. (*Interruption*). I will announce it after the Question Hour. Question No. 121.

National Pulses Development Programme

*121. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central share for National Pulses Development Programme for the year 1989-90 was only Rs. 8 crores;

(b) if so, the reason for such a meagre allocation (2 per cent) especially when the annual imports are in the range of Rs. 440 to 450 crores;

(c) whether Government propose to utilise the NDDB's expertise in developing the oilseeds and oilseeds Market Intervention Programme to enchance production and to stabilise the prices of pulses; and

(d) if so, the details and time schedule thereof?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के लिए निधियों का आवंटन आयात मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता है। तथापि, 1990-91 के दौरान यह राशि बढ़ाकर 24.05 करोड़ रुपये कर दी गई है ताकि दलहन उत्पादन को अपेक्षित थ्रस्ट प्रदान किया जा सके।

(ग) और (घ) दलहन उत्पादन को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय आदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और बायो-टैक्नोलोजी विभाग से लिए जा रहे हैं और ऐसा विचार नहीं है कि बाजार हस्तक्षेप कार्यों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सम्बद्ध किया जाए।

SHRI VIREN J. SHAH: I am not used to have a preliminary preface before a supplementary question. But with your permission, I would like to say that pulses provide protein, and protein, from the health point of view, is the greatest need, particularly in India when nearly 75,000 to 80,000 go blind every year for lack of protein and several millions of people have mental or physical deficiencies because of lack of protein. The context here is that from 1951 when we used to have per capita 60 grams of pulses, in 1989 end, we have come down to 40 grams. These are also provisional figures. These are the Ministry's data. The data itself are provisional for the last nine years. In that con-

text, one point is, in the last 20 years, from 11 million tonnes of pulses production, we have advanced to only 12 million tonnes, that is, 0.8 per cent growth and this was our taget for the Second Five-Year Plan end. At the end of the Seventh Five-Year Plan, even in a twenty-five year period, we have not reached really even 12 million tonnes. At the same time, apart from the health aspect and the need, we are concerned about the poor people. All of us profess to be so. We are importing pulses worth Rs. 440 crores which may go up to Rs. 500 crores or more becuase the rupee-value is going down. We have to view this matter not only from the point of view of the need for protein for the people but from the point of view of saving foreign exchange and imports. In the reply, the hon. Minister says that the allocation of funds has been raised to Rs. 24 crores. That seems to be not reasonsable at all. I have got certain calculations made that even if Rs. 55 to Rs. 60 crores are given, there could be a saving in foreign exchange up to nearly Rs. 300 crores per annum. It could be worked out. I am not going into the details. Is the Government, therefore, thinking of doing that? And here, to Question No. 131, there is the answer that Rs. 300 to Rs. 400 crores are lost every year on seeds. But we are not prepared to give even Rs. 50 crores. Will the Minister kindly consider in this background? Then I will ask my second supplementary.

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जितनी दाल प्रति व्यक्ति उपलब्ध होनी चाहिए श्री खपत के लिए उतनी देश में उपलब्ध नहीं है, यह सही है और जो उत्पादन होता है वह जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए आयात करना पड़ता । यह माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है। जो विशेषज्ञों का दल है, उस ने यह बताया है कि उपभोग स्तर पर दालों की आवश्यकता 47 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है और उत्पादन स्तर पर 53 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन अगर लक्ष्य रखा जाए तो इस पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर लगभग 17.6 मिलियन मीट्रिक टन दाल की जरूरत होगी और इस शताब्दी के अन्त तक 21 मिलियन मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी। इस में कमी है, इस बात को उत्तर में भी स्वीकार किया गया है। जहां तक उत्पादन को बढ़ाने का सवाल है, तो सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और पहले जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उस में जो एलोकेशन लगभग 8 करोड़ रुपया था, उस को बढ़ाकर इस वर्ष 24 करोड़ कर दिया गया है। खासकर जो नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोग्रगम है, उस में लगभग 18 करोड़ रुपए और एस०एफ पी० पल्सेज जो हैं, उस में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री वीरेन्द्र जे० शाह : 50 करोड़ क्यों नहीं कर सकते ?

श्री नितिश कुमार : इस के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सभापति महोदय, यह विचार किया जा रहा है कि जिस प्रकार तिलहन के मामले में टैक्नोलोजी मिशन आन आइल सीड्स है, उसी प्रकार पल्सेज के मामले में टैक्नोलोजी मिशन आन पल्सेज हो ताकि पूरी एक्टिविटी को कोआर्डिनेट किया जा सके और जो दलहन है, उसका उत्पादन अधिकतम किया जा सके। इसके लिए सरकार सचेष्ट है।

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, in the whole world the lowest yield per hectare of pulses is in India. In the last 30 years so far as cereals are concerned, particularly wheat, we have increased our production and productivity by 230 per cent and for rice over 75 per cent, but in the case of pulses there has been no increase—the lowest yield per hectare, apart from the lowest per capita consumption. In his context the Minister has replied earlier that there is no question of associating the NDDB in the Market Intervention Programme. The reason why I have suggested this or asked this question about NDDB is that NDDB has proved that we had

similar problem in oilseeds in late seventies and early eighties, and through the entire co-operative movement the kind of technology that the NDDB brought in for oilseeds which is an important thing today, we have also to import it, and that there is the problem of price rise. Why is it that the Government is not considering setting up of more co-operatives on NDDB model all over India and taking advantage of it? There are two problems that the farmers face in this regard. There is an uncertainty of weather and an uncertainty of price. The NDDB experiment enables the oilseeds farmers to move ahead and improve the situation though today we are not self-sufficient but both these, the oilseeds and the pulses, provide the protein. And you heard Anant Ram Jaiswalji taking about *dal* when he spoke about price and how in the prison the prisoner who had not found and taken *dal* for three or four months and had not even tasted the *dal*—and the jail *dal* which was inedible for him—drank three or four katories of it. Now in that context would you kindly move from this particular attitude given in your reply, (c) or (d) whatever it is, that it is not contemplated to associate it in market intervention activities. Sir, through you, I want to ask, where we have a proven experience of NDDB achieving something in oilseeds field, why it is that the Government is hesitant on doing the same experiment for pulses when the most dismal record of India in agriculture is in pulses. As I have mentioned earlier, in 50 years our productivity per hectare has gone down rather than going up.

श्री नितिश कुमार : सभापति, महोदय, जहां तक प्रोडक्टिविटी का सवाल है, वह पिछले वर्षों में प्रति हैक्टेयर बढ़ी है। उसके फिगर्स मेरे पास हैं, वह दिए जा सकते हैं।

श्री वीरेन जे० शाह : 0.8 परसेंट बढ़ी है।

श्री नितिश कुमार : कम बढी है, इस में कोई शक नहीं है और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए...

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि कम बढ़ी है।

श्री वीरेन जे० शाह : 0.8 परसेंट।

श्री सभापति : ज्यादा बढ़ी तो नहीं कहेंगे, वह भी कह रहे हैं कि कम बढ़ी है।

श्री नितिश कुमार : माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि थोड़ बढ़ी है। मैं भी कह रहा हूं कि कम बढ़ी। इस को और बढ़ाने का सरकार का इरादा है। जहां तक मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन चालू करने का सवाल है, इसके बारे में विचार चल रहा है। एन०डी०डी०बी० ने ऑइल सीड के बारे में जो अच्छा काम किया है और जो उनका एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज से भी हम लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन सवाल एजेंसी का है। हम ने जो जवाब दिया है, उस में एजेंसी के रूप में एन०डी०डी०बी० को इनवाल्व करने का विचार नहीं है क्योंकि एन०डी०डी०बी० के पास आलरेडी बहुत सारे काम हैं। लेकिन "नाफेड" को एजेंसी बनाया जाय मार्केटिंग इंटरवेंशन के लिए, इसके बारे में विचार चल रहा है।

श्री वीरेन जे० शाह : अलग-अलग स्टेट्स में कोआपरेटिव... (*व्यवधान*)

श्री नितिश कुमार : नाफेड जब है तो कोआपरेटिव सेक्टर का स्वाभाविक इनवाल्वमेंट है। नाफेड तो एपेक्स बाडी है। उसका स्वाभाविक रूप से विचार चल रहा है और अंतिम निर्णय शीघ्र ही होनेवाला है।

श्री वीरेन जे० शाह : सर, मेरा जो एक सवाल था कि मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर की जो किताब है—"एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लेन्स", जो फरवरी 1990 में प्रकाशित हुई है, उसमें 1981 से प्रोवीजनल डेटा दिए हैं। मैंने पूछा था कि इनके पास पूरे मुकम्मिल डेटा क्यों नहीं हैं? इसका जवाब नहीं दिया है।

श्री नितिश कुमार : दस साल का आंकड़ा उपलब्ध है, वह दस वर्षों का स्टेटिस्टिक दिया गया है।

श्री सभापति : पिछले नौ सालों से क्यों नहीं बना ? वे यह पूछना चाहते हैं । तो वह अभी तैयार नहीं हो पाया होगा या कलेक्शन नहीं हो पाएगा ।

श्री नितिश कुमार : इसको हम देख रहे हैं, सर ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Fortunately or unfortunately we are not basically non-vegetarian people and we are not accustomed to eating snakes, crabs, cows and other kinds of non-vegetarian food. So necessarily we have to depend on pulses for our essential aminoacids as well as proteins. For want of proteins, as has been mentioned by my friend, there is mental retardation and retardation of growth in the children of our country. In the world market also there are very few countries offering to sell pulses. It is not readily available in the world market. Pulses are grown to some extent in dry land areas. But that is less than 40 per cent. More than 50 per cent of pulses are produced in the rice fallows as rabi crop after the first crop is harvested. What is the proposal or scheme available with the Government to raise the production of pulses in the rice fallows in the rabi season under the ICAR and in the Agricultural Universities? What are the schemes envisaged and what are the schemes under implementation to produce more and more pulses and to enhance rabi production in rice fallows?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, वह बिल्कुल जायज है, इसकी कमी को देखते हुए और यह भी सही है कि बाहर के मुल्कों में उस हद तक उपलब्ध ही नहीं होता । तो यह समस्या हमारे सामने । जहां तक इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का सवाल है, मैंने पहले ही प्रश्नों के उत्तर में बताया कि दो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं—नेशनल पल्सेस डवलपमेंट प्रोग्राम और एस०एफ०जी०पी० । इनके माध्यम से कई कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उन लोगों के बीच में, जो खासकर के एस०एफ०जी०पी० का, चना, अरहर है, जो पोटपोरर का अटेक होता है, उसको दूर करने के लिए और नेशनल पल्सेज प्रोग्राम में कई प्रकार के काम किए जाते हैं, जिसमें बीज वितरित किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, फ्रंट लाइन डेमोन्सट्रेशन किया जाता है और इन सब चीजों के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट कन्ट्रोल वर्कर्स की ट्रेनिंग, ये सारे काम किए जाते हैं, जिससे इनके चलते इसका उत्पादन ज्यादा हो । साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार कोडिनेटेड एफ़र्ट करना चाहती है । यह टेक्नोलोजी मिशन चलाकर के । सरकार का इस पर विचार चल रहा है और अंतिम निर्णय शीघ्र ही होगा ।

SHRI S. B. CHAVAN: I would like to seek information from the honourable Minister. We have shortage of pulses for a considerable time and even though Government has made efforts, I don't think Government has succeeded nor have the scientists succeeded in producing disease-resisting varieties and also hybrid varieties so far as pulses are concerned. I do not know whether it is really the question of resources which, in fact, is coming in the way or whether it is the lack of effort on the part of the scientists to evolve a special kind of variety which will increase productivity. Unless productivity is increased, I don't think that agriculturists are going to be attracted for producing pulses. And that is why it becomes all the more necessary that our scientists will have to apply their mind and see that good varieties of pulses are produced which can give them remunerative prices and also increased productivity. Unless that effort is made, I do not think that any other effort is going to be of any use.

श्री नितिश कुमार : सभापति जी, ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उन्नत किस्म के बीज इसमें निकाले जाएं और उनको अधिक से अधिक पॉपुलराइज़ किया जाए और इसीलिए ये सारे प्रोग्राम मुख्यत: बीजों के वितरण के लिए हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि अपेक्षित उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है । ज्यादातर पल्सेज की जो खेती है वह रेन फेडो एरिया

मे ही होती है, उसके चलते बहुत कठिनाई होती है, मानसून पर बहुत अधिक यह निर्भर करती है । लेकिन हम इस वर्ष कई चीजों के बारे में इसमें ध्यान दिया गया है कि अगर प्रोडेक्शन में कमी आएगी तो दूसरी तरह के जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका भी उपयोग इस मामले में हो सकता है ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Sardar Jagjit Singh Aurora.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, I think my question has already been given as a supplementary.

MR. CHAIRMAN: Very good.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, as regards the measures that are being taken, I would like to know whether there is any time-bound programme, whether they hope to see any improvement and, if so, within how much time. Has anything been worked out or are we working on general lines at the end of which we may find that the progress has not only been small, but also very small?

SHRI VIREN J. SHAH: Particularly in the 'Kisan Decade' !

श्री नितिश कुमार : यह माननीय सदस्य ने बैठे-बैठे ठीक ही कहा कि सरकार ने इसको किसान दशक घोषित किया है इसलिए हर प्रकार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार दृत संकल्प है । बीजों के भी उन्नत किस्म निकालने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं और कई उन्नत किस्म के बीजों का विकास हुआ है । अरहर में एक संकर किस्म के बीज का विकास हुआ है और जल्दी पकने वाली जातियों का भी विकास हुआ है । ये सब प्रयत्न किए जा रहे हैं और प्रयत्न फलल होंगे ऐसी हमें उम्मीद है ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Balanandan.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, there is import of edible oils on a large scale by the Government of India since we are lacking in edible oils production. May I ask the Minister one thing? We are having a lot of land and the oilseeds cultivation can be easily encouraged in the country.

MR. CHAIRMAN: The main question is about pulses.

SHRI E. BALANANDAN: I am asking about edible oils.

MR. CHAIRMAN: No. The question is about pulses only.

SHRI E. BALANANDAN: Yes, Sir. The question is about pulses. But pulses and edible oils form part of the question ... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Then everything will form part of it ...(*Interruptions*)...You ask questions about pulses. I cannot permit anything about edible oils under this. Now, the next Question. Question No. 122.

Decentralisation of CAPART

*122. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be please to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to decentralise the Council for Advancement of people's Action for Rural Technology by setting up four regional branches thereof; and

(b) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की चार क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित करके इसका विकेन्द्रीकरण करने की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं समझी गयी है ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, the National Front Government is committed to decentralising all the powers. But this process of decentra-